HRA Sazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप₇खंड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) Ma 199

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206] No. 206] नई दिल्ली, बृहस्पतिबार, अप्रैल 29, 1999/बैशाख 9, 1921 NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 29, 1999/VAISAKHA 9, 1921

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसुखना

मई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1999

सा. का. नि. 298(अ).— प्राष्ट्रपंति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

''सं० आ० 175''

महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाङ्गा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष दायित्व) संशोधन आवेश, 1999 ।

राष्ट्रपति ने, संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष दायित्व) आदेश, 1994 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) किया है, जिसमें उस राज्य के राज्यपाल द्वारा विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना के लिए महाराष्ट्र विधान मेडल द्वारा पारित प्रस्तावों को प्रभावी किया गया था;

और उक्त आदेश 1 मई, 1994 से प्रवृत्त हुआ और उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के निबंधनों के अनुसार यह 30 मई, 1999 को या उस तारीख को, जो राष्ट्रपति, इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, समाप्त होगा ;

और उक्त आदेश के अनुसरण में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोडों की तब तक के लिए स्थापना कर ली है, जब तक उक्त आदेश अर्थात् 30 अप्रैल, 1999 तक प्रवृत्त रहता है ;

और महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उक्त विकास बोर्डों को उक्त क्षेत्रों में बनाए रखने के हित में यह समीधीन समझते हुए और राज्य सरकार के अनुमोदन पर राष्ट्रपति से उक्त आदेश की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है ; अतः अब राष्ट्रपति, उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि उक्त आदेश 30 अप्रैल, 2004 तक प्रवृत्त रहेगा ।

(के. आर. नारायणन)

राष्ट्रपति

[फा. सं. 19(5)/99-विधायी-1]

रमबीर सिंह, संचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS -

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 1999

G.S.R. 298(E).—The following Order made by the President is published for general information:

THE STATE OF MAHARASHTRA (SPECIAL RESPONSIBILITY OF GOVERNOR FOR VIDARBHA, MARATHWADA AND THE REST OF MAHARASHTRA) AMENDMENT ORDER, 1999.

WHEREAS the President has, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, made the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Order, 1994, (hereinafter referred to as the said Order) giving effect to the resolutions passed by the Maharashtra State Legislature for establishment of separate Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra by the Governor of that State;

AND WHEREAS the said Order came into force with effect from the 1st day of May, 1994 and in terms of sub-clause (3) of clause 1 of the said Order it shall expire on the 30th day of April, 1999 or up to such date as the President may, by order made in this behalf, specify;

AND WHEREAS in pursuance of the said Order, the Governor of Maharashtra has set up the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra till the said Order remains in force, that is, up to the 30th day of April, 1999;

AND WHEREAS the Governor of Maharashtra considers it expedient in the interest of the said areas to continue the said Development Boards and on approval of the State Government has requested the President to extend the duration of the said Order;

NOW, THEREPORE, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, the President hereby specifies that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2004.

K.R. NARAYANAN President.

[F. No. 19(5)/99-L. I]

RAGHBIR SINGH, Secy.